down when the interest and the principal are going to increase year after year.

Textile processing units facing closure in Amritsar

*24. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:t

SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Hindustan Times dated January 13 last to the effect that about hundred odd textile processing units in Amritsar (providing employment to about 70,000 workers) are facing closure due to illogical Central excise duty regulations;

(b) whether it is a fact that the Amritsar Textile Printers' and Processors' Association has requested the Central Government to shift the burden of excise duty from textile processing to yarnfibre manufacturing and if so, what are the facts thereof; and

(c) what is Central Government's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) The Government is aware that a news item entitled "Textile units face closure", had appeared in the Hindustan Times, dated the 15th January. 1989.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Harvendra Singh Hanspal.

(b) The Amritsar Printers' and Pro cessors' Association, in their letter dated the 23rd January, 1989, have suggested shifting of the central excise duty on synthetic fibrics to the yarn or fibres. The Association have also suggested alterna tively restructuring and reduction of ex cise duty on synthetic fabrics.

(c) In view of the forthcoming Union Budget, it would not be possible to indi cate Government's response to the sug gestions.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: चेयरमैन महोदय, जो क्वेश्चन मैंने पूछा वही इन्होंने रिपीट कर दिया अपने जवाब में और लास्ट में कह दिया कि बजट के कारण कोई सूचना नहीं दे सकते, बता नहीं सकते।

श्री सभापति: 28 तारीख को बता देंगे।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं....

MR. CHAIRMAN: Everything is under consideration.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: इंटीमेशन तो दे सकते हैं।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: चेयरमैन महोदय, या तो ऐसा हो कि यह क्वेश्चन बाद में ले लिया जाय ताकि दुबारा पूछने का मौका मिल सके।

श्री सभापति: आप ऐसा करें कि अगर 28 को जवाब न दें तो फिर सवाल कर लीजिये।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर बारी नहीं आयेगी।

श्री सभापति: सेशन मई तक चलेगा।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दिया जाय।

श्री सभापति: मैं यह कह नहीं सकता कि बता दें कि बजट में क्या आ रहा है।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

SHRI A. G. KULKARNI. Sir, he is quite right. It is like *Kumbh Mela.* It takes 12 years to get 2nd or 3rd number in the List of Questions. Please transfer the question so that he can ask the question after the Budget.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, 1 get a smell from the Minister's reply that questioners point is being met.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: अगर पोस्टपोन नहीं हो सकता है तो मैं एक-दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं।

श्री सभापति: पूछ लीजिये अगर बजट को टच न करता हो।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: उसको तो ना कह देंगे।

श्री सभापति: पूछिये आप अपना सप्लीमेंटरी।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब आप एक्साइज ड्यूटी किसी प्रोडक्ट पर, किसी चीज पर लगाते हैं तो उसका मंतव्य क्या है? मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब आप एक्साइज़ ड्यूटी लगाते हैं तो उसका मंतव्य क्या है? क्या उसका मंतव्य यह है कि आप उससे कुछ फ़ण्ड्ज़ कलेक्ट करना चाहते हैं या उसका मंतव्य छोटे-छोटे मेनुफेक्चरर्ज़ को तंग करना है?

SHRI AJIT PANJA: Sir, the intention is three-fold. First is to raise revenue. Second is to protect those indigenous industries and other industries which need our protection like Khadi, hand-loom and others And the third, Sir, is to see, like here, the additional excise duty put in, the entire amount which is raised in lieu of sales tax goes buck to the States, the whole of it goes back. Nothing is retained. Sir, if it is basic excise duty, then something is retained for the Union and some portion—it is 55:45—is given to the States. These are the three main intentions.

श्री सभापति: उनको तंग करना बिलकुल नहीं है यह आपका मतलब है।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: साइलेंट रहने का मतलब है, ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा इससे पहले दो तीन साल बजट आते रहे हैं, अब वे हमारे यहां नहीं है उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा जो वित्त मन्त्री थे उन्होंने बहुत रेकलेसली एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी बगैर सोचे समझे लगा दी...

श्री सभापति: इसके बारे में जब बजट आएगा तब कहियेगा। अब आप सवाल कीजिये।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि जैसे अमृतसर यूनिट्स की बात हो रही थी तो क्यों नहीं ऐसा करते की यार मेनुफेक्चरर्ज़ के ऊपर फाइबर्स मेनुफेक्चरर्ज़ के ऊपर ड्यूटी लगाएं जितनी चाहे बढ़ा दें क्योंकि जो छोटे-छोटे प्रौसेसर्स और वीवर्स सैंकड़ों हज़ारों की संख्या में हैं जो एक्साइज़ ड्यूटी दे नहीं सकते है या जिनके पास इतना इन्तजाम नहीं है कि वे एक्साइज़ इंस्पेक्टर्ज की जेब भर सकें या उनका मुंह बन्द कर सकें (**व्यवधान**) इसी तरह से ट्रक बाडी बिल्डर्ज़ हैं। चार आदमी इकट्ठे हो कर के सड़क के किनारे पर ट्रकों की बाडीज़ बना लेते हैं उनके ऊपर भी एक्साइज़ ड्यूटी लगा दी गई। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़ी-सी एक्साइज़ ड्यूटी चेसिस पर बढ़ा दें? जब मैंने यह सवाल किया कि क्या यह तंग करने का मंतव्य है तो मन्त्री जी ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं यह चाहूंगा कि मन्त्री जी उसका भी जवाब दें (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: If it is a suggestion for action, the suggestion will be noted. Put your question.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: होता यह है कि एक्साइज़ ड्यूटी का इवेज़न करना पड़ता है। जो आदमी आनेस्ट रहना चाहता है वह भी आनेस्ट नहीं रह सकता क्योंकि सिस्टम इस किस्म का एक्साइज़ ड्यूटी लगाने का है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी कम से कम यह एश्योर करेंगे कि इस

बजट में इन बातों का वे ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे?

SHRI AJIT PANJA: Sir, I cannot say anything about the Budget because I do not want to lose my job.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Just like the NTR Cabinet.

SHRI AJIT PANJA: Sir, there is no harassment whatsoever. Whenever any case of harassment is brought to our notice, immediate remedial measures are taken. But, of course, Sir, in the case of those who are evaders of excise duty, we enforce the law very strictly. Sir, so far as bus body builders are concerned, this does not fall either under yarn or fabric or fibre.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Mr. Chairman, Sir, taking the cue from the hon. Member who has put the question, I just want to say that as too many controllers vitiate the various control laws, similarly, it is the staff—whatever the hon. Minister may say other wise—whose visits work hardship for the petty manufacturers who arc no better than the Khadi-producing units. It is a different question that if a complaint is brought to the notice of the Minister, he would take action on it.

MR. CHAIRMAN: Put your question.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, in a word I would say. Any small manufacturer cannot take the risk of complaining to -the Minister about the unreasonable demands of the staff. I would like to know from the hon. Minister as to what mointoring system he has devised to see that members of the staff of the excise department, etc., do not raise other questions which do not pertain to them and do not make those demands on the poople which are difficult to meet.

SHRI AJIT PANJA: Sir, wherever the small and medium manufacturers, in fact, anyone finds that anything excessive has been done or hardship has been caused, not necessarily they can approach only the Minister, they can approach the Members of Parliament, the representatives of people. Sometimes they bring it to my notice. We immediately take remedial measures.

So far as monitoring is concerned, our vigilance cells and intelligence cells are operating there. If we find in our independent vigilance cell that there been anything wrong by any individual officer or group of officers/ we do take steps.

श्री मीर्जा इर्शादबेग: सभापति जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि तंग करना तो मैं नहीं चाहता। लेकिन फारसी में कहा जाता है कि "तंग आमद तो जंग आमद"। तंग करेंगे तो जंग चलेगी। जंग बहुत जगह पर चल रही है। मैं जानकारी यह लेना चाहता हूं जैसा कि मंत्री जी ने यह कहा कि....

श्री सभापति: ये जंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मीर्जा इर्शादबेग: अच्छा है वह अगर हो जाये तो। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी एक मंशा यह है कि उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाय, तो मैं उस जगह से आता हूं जहां की नगरी को कभी मानचेस्टर आफ इंडिया कहा जाता था, वहां आज पूरी मिलों की चिमनियां बंद हैं और इस पालिसी के कारण कई नुक्सान हुए हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन की हमारी मंशा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में इस की वजह से जितना भी आपका रेवेन्यू कलेक्शन है उससे ज्यादा उसमें चोरी होती है। मैं हंसपाल जी के साथ सम्पूर्ण अपनी सहमति व्यक्त करता हूं कि यहां एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। अगर इस यार्न पर ड्यूटी लगा दी जाये तो मैं समझता हूं कि यह जो चोरी है वह बंद कर पायेंगे और उनकी एक जो मंशा है कि रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो पायेगा तो मैं समझता हूं कि उससे रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो पायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना

चाहता हूं कि यह एक हमारी भावना है और मैं उसी जगह से आता हूं तथा अभी मान्यवर मैं वहां गया था और कितने ही लूम सेक्टर्स को मैंने परसनली जाकर विजिट किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो वहं मंशा है उस मंशा का मंत्री जी ध्यान रखें और आने वाले बजट में इसकी संतुष्टि कर दे।

MR. CHAIRMAN: Kindly take note of the suggestions.

SHRI AJIT PANJA: Noted, Sir.

MR. CHAIRMAN: Next question.

Call for hartal in Kashmir Valley on Republic Day

25. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Kashmir Valley observed hartal on the 26th January this year on a call given by secessionist organisations;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken by the Central Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Hartal was observed in some parts of the valley.

(b) The call for hartal on 26th January, 1989 evoked partial response from the people. Business establishments in some places in the valley remained closed on that day.

(c) 'Public Order' being a State subject, it is primarily for the State Government to take appropriate action. The State Government were requested to take necessary preventive and precautionary measures to thwart any untoward incidents on the Republic Day. Assistance wherever asked for was also provided.

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Sir, Jammu and Kashmir is a sensi-tive border State. Fundamentalists, secessionists and anti-India plements, under pro-Pakistan organisations are trying to create law and order problem and they are trying to convert a paradise on the earth into a living hell. October 27, 1988 was observed as a black day by the secessionist organisations while 41 years ago on that day the State had acceded to India. The JKLF, Azad Muslim conference headed by Chowdhury Sultan Mohammad had organised several anti-India demonstrations in New York and several European capitals in the past. It is reported that the secessionists have received training in the use of sophisticated weapons and in guerilla warfare in camps in occupied Kashmir and in Pakistan. The training was imparted by officers of Pakistan army's Field Intelligence Unit (FIU) and Inter-Services Unit (ISU). Camps are allegedly located at Muxaffarabad, Lohabutt, Ojehra, Aliapur, Kachigarhu, Aliabad and Faisalabad. It seems that Pakistan now wants to get Kashmir on instalment basis. So, I would like to know whether the Government is aware of all these facts, and if so, what steps were taken by the Government in the past and what action is proposed to be taken by the Government in future to suppress these fundamentalists, secessionists, anti-India elements and pro-Pakistan organisations.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Government is aware of the activities of the secessionist elements which are pro-Pakistan. In 1987 their activities were more or less under control but in the latter half of 1988 and in the first couple of months in 1989 their activities seem to have gained ground. We are aware of their activities. The Home Minister has had a couple of meetings with the Chief Minister of Jammu and Kashmir. Officers of the Jammu and Kashmir Government